लैंगिक संवेदनशील न्याय: भाषा से आगे व्यवहार तक

न्यायपालिका व सामाजिक न्याय | समाचार संदर्भ: 3 अगस्त 2026

न्याय केवल अंतिम निर्णय का नाम नहीं है। अदालत तक पहुँचने वाले व्यक्ति को सुनवाई के दौरान सम्मान, सुरक्षा और अपनी बात कहने का वास्तविक अवसर भी चाहिए।

खबरों में क्यों

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर 3 अगस्त 2026 को “Judgments and Gender: Sensitivity and Compassion in Writing Judgments” रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने इसे तैयार किया। यह लैंगिक रूढ़ियों से मुक्त भाषा के साथ संवेदनशील न्यायालय-व्यवहार पर जोर देती है।

द्वितीयक पीड़ितकरण क्या है?

अपराध के बाद सहायता और न्याय पाने की प्रक्रिया ही यदि अपमानजनक सवाल, अनावश्यक दोहराव या पहचान के खुलासे से दोबारा मानसिक आघात दे, तो इसे द्वितीयक पीड़ितकरण कहते हैं। संवेदनशील प्रक्रिया का लक्ष्य यह नुकसान घटाना है, आरोप को बिना प्रमाण स्वीकार करना नहीं।

मुख्य तथ्य

विशेषज्ञ अध्ययन का आधार: समिति ने देशभर के 125 विचारण न्यायालयों के निर्णयों का विश्लेषण किया और राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया ली। निष्कर्षों को पूरे देश के सभी न्यायाधीशों का सांख्यिकीय चित्र नहीं मानना चाहिए।

सम्मानजनक भाषा: निर्णय में व्यक्ति के चरित्र, कपड़ों या कथित नैतिकता पर रूढ़िबद्ध टिप्पणी के बजाय कानूनी प्रश्न, साक्ष्य और अधिकारों पर ध्यान जरूरी है। सरल भाषा पीड़ित, गवाह और सामान्य पाठक को निर्णय समझने में सहायता देती है।

सुनवाई के दौरान सहायता: रिपोर्ट कानूनी सहायता की उपलब्धता जाँचने, गोपनीयता, परामर्श, गवाह-सुरक्षा और सम्मानजनक वातावरण पर जोर देती है। अनावश्यक प्रतीक्षा कम करना और बुनियादी सुविधा देना भी न्याय तक पहुँच का हिस्सा है।

दस्तावेज का दर्जा: इसे नए दंड कानून या प्रत्येक सिफारिश को स्वतः नया वैधानिक आदेश न मानें। रिपोर्ट पहले से मौजूद कानूनों और न्यायिक निर्णयों को भी जोड़ती है; प्रत्येक उपाय का कानूनी आधार अलग पढ़ना चाहिए।

निष्पक्ष सुनवाई और संवेदनशीलता साथ कैसे चलें?

जिरह का उद्देश्य: साक्ष्य की विश्वसनीयता परखना जरूरी है, पर अपमान या भय पैदा करना उसका उद्देश्य नहीं। रिपोर्ट संवेदनशील गवाही के दौरान संरक्षण के साथ अभियुक्त के अधिकार सुनिश्चित करने का संतुलन भी स्पष्ट करती है।

संस्था पर भरोसा: यदि गवाह अदालत में आने से डरें या बार-बार निरर्थक प्रतीक्षा करें, तो साक्ष्य सामने आने में बाधा पड़ सकती है। समय का सम्मान और साफ सूचना प्रक्रिया में भागीदारी आसान बनाते हैं।

प्रशिक्षण की जरूरत: केवल निषिद्ध शब्दों की सूची पर्याप्त नहीं। स्थानीय भाषाओं, सामाजिक असमानताओं और मानसिक आघात की समझ को न्यायिक प्रशिक्षण तथा रोजमर्रा के प्रशासन में जोड़ना होगा।

विश्लेषण और आगे की राह

सुधार को शब्दावली बदलने तक सीमित करने से वास्तविक अनुभव नहीं बदलेगा। अदालत में कानूनी सहायता, सुलभ सूचना, सुरक्षित गवाही की व्यवस्था और अनावश्यक स्थगन घटाने पर ध्यान देना चाहिए। संवेदनशीलता का मूल्यांकन केवल प्रशिक्षण की संख्या से नहीं, सेवाओं की उपलब्धता और गवाहों के अनुभव से भी किया जा सकता है। साथ ही प्रमाण का परीक्षण और निष्पक्ष सुनवाई कमजोर नहीं होने चाहिए। करुणा प्रक्रिया को मानवीय बनाए, निर्णय में पूर्वग्रह का नया रूप न बने।

अवधारणा में अंतर

पीड़ित के प्रति सम्मान और अभियुक्त को पहले से दोषी मानना अलग बातें हैं। संवेदनशील प्रक्रिया साक्ष्य-आधारित निर्णय की सहायक है, उसका विकल्प नहीं।

मेंस दृष्टि

उत्तर में गरिमा, न्याय तक पहुँच और निष्पक्ष सुनवाई जोड़ें। केवल भाषा-सुधार के बजाय व्यवहार, सहायता-व्यवस्था और जवाबदेही पर उपाय दें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

“लैंगिक संवेदनशील न्याय केवल निर्णयों की भाषा सुधारने से नहीं आएगा।” न्यायिक प्रक्रिया में गरिमा और निष्पक्ष सुनवाई का संतुलन रखते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: व्यक्ति की गरिमा और न्याय तक पहुँच को लैंगिक संवेदनशील प्रक्रिया का आधार बताएँ; संवेदनशीलता को साक्ष्य-आधारित निष्पक्ष निर्णय की सहायक रखें।

मुख्य भाग में: रूढ़िबद्ध भाषा के साथ भय, निरर्थक प्रतीक्षा और प्रक्रियात्मक आघात की समस्या समझाएँ। कानूनी सहायता, गोपनीयता, परामर्श, गवाह-सुरक्षा और सुलभ सूचना के उपाय दें। प्रशिक्षण में स्थानीय भाषा तथा सामाजिक असमानता की समझ जोड़ें। सम्मानजनक जिरह के साथ साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण और अभियुक्त के अधिकार सुरक्षित रखना जरूरी बताएँ।

निष्कर्ष में: सुधार को शब्द-सूची या प्रशिक्षण की संख्या तक सीमित न रखें; सहायता की उपलब्धता और गवाहों के अनुभव से परिणाम परखें। गरिमा और निष्पक्षता साथ बढ़ें, पर संवेदनशीलता को पूर्वनिर्धारित दोष या प्रमाण की जाँच का विकल्प न बनने दें।

स्रोत

- उच्चतम न्यायालय: रिपोर्ट का आधिकारिक प्रकाशन, 3 अगस्त 2026
- आधिकारिक रिपोर्ट: Judgments and Gender, 2026
- नई रिपोर्ट के उद्देश्य पर स्वतंत्र व्याख्या, अगस्त 2026

याद रखें: संवेदनशील प्रक्रिया का लक्ष्य गरिमा और निष्पक्षता को साथ सुरक्षित करना है।